कृषि तकनीक सीखने हुड्डा इजराइल गये

चंडीगढ़ (म.मो.) हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा अपने कृषि विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्रों का सत्यानाश करके अब नयी कृषि तकनीक सीखने के लिए इजराइल की यात्रा पर चले गये गये। हुड्डा जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने काफ़ी विदेश यात्रायें की हैं। शायद ही किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो जिसने इनके बराबर विदेश यात्रा की हो। हुड्डा बराबर इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे उन्हें विदेश यात्रा का अवसर मिले। इस बार इन्होंने बहाना तलाशा कृषि तकनीक सीखने का। हुड्डा का कहना है कि इजराइल की कृषि तकनीक दुनिया की बेहतर कृषि तकनीकों में से एक है। वे कम पानी और संसाधनों की काफ़ी बचत कर अधिक से अधिक उपज हासिल करते हैं। हुड्डा का कहना है कि जब वे इजराइल से वहां की कृषि तकनीक सीख कर आयेंगे तो यहां कृषि का चहुंमुखी विकास करवायेंगे।

मुख्यमंत्री जब इजराइल की यात्रा पर एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ गये। ये वहां चंद दिन रहे और फ़िर वापस आ गये। यहां यह सवाल उठता है कि थोड़े दिनों में हुड्डा ने इजराइल की नयी कृषि तकनीक कैसे सीख ली। उनका ज़्यादा समय तो वहां राजनेताओं और अधिकारियों से ही मिलने में चला गया। फ़िर कृषि तकनीक सीखने का पर्याप्त समय कैसे मिला? इसके अलावा, यह मुख्यमंत्री का काम नहीं है कि वह किसी क्षेत्र में नयी तकनीक सीखने के लिए किसी खास देश की यात्रा करे। किसी खास क्षेत्र में नयी तकनीक सीखने के लिए उस विषय का पहले से आधारभूत ज्ञान होना जरूरी है। इसके अभाव में व्यक्ति नयी तकनीक नहीं सीख सकता है। क्या हुड्डा को कृषि विज्ञान में महारत हासिल है? अगर उन्हें कृषि विज्ञान की जानकारी नहीं है तो वे नयी

घरेलू तकनीक का किया विनाश, बाहर से लाने गए विकास

कृषि तकनीक कैसे सीख पायेंगे और फ़िर यहां के किसानों को कैसे वह तकनीक सिखा पायेंगे? अगर मुख्यमंत्री ही हर क्षेत्र में नयी तकनीक सीखने के लिए विदेशों की यात्रा और वहां प्रवास करने लगे तो राज्य के शासन का काम कौन देखेगा?

अगर मुख्यमंत्री इजराइल की कृषि तकनीक से प्रभावित थे और उसे राज्य में लागू करना चाहते थे तो उन्हें चाहिए था कि इसके लिए वे राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के प्रो.फ़ेसरों और शोधकर्ताओं को वहां भेजते जो छ:महीने-साल भर वहां रह कर नयी तकनीक का पूर्ण ज्ञान हासिल करते और फ़िर वापस आकर उसे कृषि के क्षेत्र में व्यावहारिक तौर पर लागू करते।अथवा वहां के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके अपने विशेषज्ञों को वांछित ट्रेनिंग दिलवाते। यही एक सही तरीका हो सकता है, वरना एक मुख्यमंत्री किस-किस क्षेत्र में नयी तकनीक सीखने के लिए कितने देशों का दौरा करता रहेगा? यहां तो विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में रोज ही नयी-नयी उपलब्धियां विदेशों में सामने आ रही हैं। क्या हुड्डा के सलाहकार उन्हें उचित सलाह और मागदर्शन नहीं देते या वे भी उनकी जी-हजूरी करने में लगे रहते हैं? लगता तो ऐसा ही है। हुड्डा के सलाहकार भी यही सोचते हैं कि चलो मुख्यमंत्री के साथ विदेश यात्रा का मौज ले लिया जाये। अगर हुड्डा के सलाहकार ईमानदार एवं कर्त्तव्यनिष्ठ होते तो कृषि तकनीक सीखने के लिए कभी उन्हें इजराइल जाने की सलाह नहीं देते, बल्कि इसके लिए वे कृषि विज्ञान में पारंगत किसी विद्वान को वहां भेजने की सलाह देते।

साफ़ ज़ाहिर है कि हुड्डा कृषि तकनीक सीखने के बजाय मौज-मजा लेने के लिए इजराइल गये हैं। वैसे भी विदेश यात्रा किये उन्हें काफ़ी दिन हो गये थे। इस यात्रा पर निकलने से पहले हुड्डा यदि यह भी बताते कि पिछली यात्राओं से वे क्या सीख कर आये और उन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित किया तो ज़्यादा बेहतर होता।

हुड्डा साहब को किसी ऐसे देश की भी खोज करनी होगी जहां उन्हें अक्ल के इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा सके। इनकी बेअक्ली का एक ताज़ा-तरीन उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला है। हरियाणा सरकार की एक एजेंसी हेफेड 286 करोड़ रुपये खर्च कर के ऐसे प्लेटफॉर्म बनवा रही है जिन पर खुले आसमान के नीचे गेहूं की बोरियों के ढेर लगाये जायेंगे। विदित है कि किसान की मेहनत से पैदा किये गये गेहूं और जनता के पैसे से उन्हें खरीद कर हर वर्ष खुले आसमान के नीचे तिरपालों से ढक कर रख दिया जाता है जो लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वैसे तो गोदामों के विकल्प के तौर पर इस तरह के प्लेटफॉर्मों को बनाने का कोई औचित्य नज़र नहीं आता, लेकिन इन प्लेटफॉर्मों के बनाने में जो सरकारी तंत्र की बेवकूफ़ियां, लापरवाहियां ध्यान देने योग्य हैं। इन प्लेटफॉर्मों को बनाने का काम जो गत वर्ष जून-जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए था, उसे इस वर्ष (26 फ़रवरी 2011) को शुरू किया गया जिसे 10 अप्रैल तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। विदित है कि इस समय पर राज्य भर के भट्ठों में बची-खुची घटिया किस्म की ईंटें ही उपलब्ध होती हैं और वे भी अति महंगे दामों पर। इसके अतिरिक्त इतने कम समय में न तो मिट्टी की विधिवत भराई हो सकती है और न ही कार्यों की उत्तम गुणवत्ता को कायम रखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप इतनी भारी रकम खर्च कर के बनने वाले प्लेटफॉर्म साल भर भी नहीं ठहर पाते। इसके चलते यही प्रक्रिया फ़िर दोहरायी जायेगी और दशकों से दोहरायी जा रही है।

राज्य में उपेक्षित है क्रिकेट

हरियाणा क्रिकेट संघ को रणबीर महेन्द्रा ने अपनी बपौती बना लिया

भारत ने 28 वर्ष बाद क्रिकेट का विश्व कप जीता तो पूरे देश में विजयी टीम के सदस्यों को सम्मानित करने का दौर चल पड़ा। हर राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए नकद एवं अन्य पुरस्कारों की घोषणा करनी शुरू कर दी। ऐसा करने की एक तरह से होड़ लग गई। ऐसे में भला हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कैसे पीछे रह जाते, क्योंकि ये अपने आप को इस देश में सबसे बड़ा खेल प्रेमी मुख्यमंत्री समझते हैं। पर अफसोस! विश्व कप जीतने वाली टीम में हरियाणा से कोई खिलाड़ी था ही नहीं। ऐसे में दो जाट खिलाड़ियों - वीरेन्द्र सहवाग और आशीष नेहरा को मूलत: हरियाणा का बताते हुए उन्होंने इनके लिए पुरस्कारों की घोषणा कर ही दी और एक तरह से तय कर दिया कि हरियाणा जाटों का राज्य है। लेकिन मुख्यमंत्री को शायद यह पता नहीं कि ये दोनों खिलाड़ी दिल्ली मूल के हैं।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को हरियाणा क्रिकेट संघ में हो रही धांधलियों की ओर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से हरियाणा के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा खो रहे हैं। विदित है कि हरियाणा के कपिलदेव ने ही 28 वर्ष पूर्व भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए विश्व कप जीता था। इसके अतिरिक्त चेतन शर्मा, विजय यादव, अजय रतरा, जोगिन्द्र शर्मा और अमित मिश्रा और अजय जडेजा समय-समय पर भारतीय टीम में राज्य का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं।

हरियाणा क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव रणबीर महेन्द्रा जो पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बंसीलाल के पुत्र हैं, ने कई वर्षों से इस संघ पर कब्ज़ा जमा रखा है। अब सचिव उनका पुत्र अनिरुद्ध है। इस संगठन को वे पूरी तानाशाही के साथ चला रहे हैं। उन्होंने संघ का संविधान इस तरह का बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री तो बन सकता है,परंतु हरियाणा क्रिकेट संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता। इसमें रणबीर महेन्द्रा ने 80 स्थायी सदस्य बना रखे हैं और प्रत्येक ज़िला इकाई का एक-एक वोट है।

स्थायी सदस्यों में घरेलू नौकर, ससुराल के रिश्तेदार एवं इसी तरह के सभी लोग हैं। इस पर भी ऐसा भय कि सालाना आम सभा अपने घर पर रखते हैं। इस तानाशाही रवैये में प्रमुखता

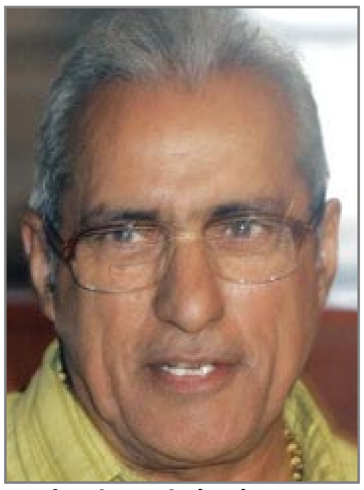

रणबीर महिन्द्रा : क्रिकेट के तानाशाह

अपनी गद्दी बचाये रखने की है। इन्होंने खिलाड़ियों और खेल को बढ़ावा देने में कभी रुचि नहीं दिखाई। फ़रीदाबाद एवं चंडीगढ़ को तो बिल्कुल अछूत बना कर रख दिया गया है। कितना भी अच्छा खिलाड़ी यदि इन ज़िलों से हो तो कभी हरियाणा से खेल नहीं सकता। सभी खिलाड़ी आतंक के साये में खेलते हैं। पता नहीं, कब 'महामहिम' का कोई चमचा नाराज़ हो जाये और धमका दे। धमकी भी गाली के साथ और इस शैली में कि 'देखता हूं तू कैसे सेलेक्ट होता है।' सेलेक्शन हो या हिसाब-किताब, सभी काम रणबीर महिन्द्रा अपने घर से ही करते हैं। अब ऐसे धौंस-पट्टी और तानाशाही वाले माहौल में कोई खिलाड़ी कैसे अपनी प्रतिभा दिखा सकता है?

हरियाणा के कई खिलाड़ी अन्य प्रदेशों में जा कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं जिनमें से प्रमुख हैं इरेश सक्सेना जो पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी जोन से खेल रहे हैं। मनविन्दर बीसला हिमाचल प्रदेश की कप्तानी कर रहे हैं एवं आईपीएल में कलकत्ता नाइट राइडर्स से खेल रहे हैं। एक वर्ष कप्तान बना कर अगले ही वर्ष टेस्ट खिलाड़ी अजय रतरा को टीम से निकाल दिया गया। वे अब गोवा राज्य को अपनी सेवायें दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त विक्रम धारीवाल, शफ़ीक खान, इशान गंडा, धर्मेन्द्र फागना आदि कई प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं दे कर इनकी प्रतिभा को कुंद कर दिया गया और आज राज्य की टीम में खिलाड़ियों का टोटा हो गया है। दूसरे राज्यों से खिलाड़ियों को भाड़े ला कर टीम की खानापूर्ति की जा रही है। इसके अलावा वित्तीय अनियमितताओं को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। रोहतक-भिवानी रोड पर गांव लाहली में क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया है जिसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने करोड़ों रुपये का अनुदान दिया है। इस स्टेडियम का कोई उपयोग नहीं होता। यदि बोर्ड में वोटों की राजनीति न होती तो इस जगह पर स्टेडियम बनाने के लिए अनुदान नहीं मिलता। यही नहीं, प्रति वर्ष फ़र्जी कैंप लगाने एवं प्रतियोगितायें करवाने के नाम पर लाखों का घोटाला किया जाता है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का अनुदान खेल के प्रसार, जूनियर प्रतियोगिताओं और मूलभूत संरचनाओं के विकास के लिए देता है। पर रणबीर महेन्द्रा ने इन रुपयों का कितना सदुपयोग खेल के विकास के लिए किया है, इसे सारा राज्य जानता है। हुड्डा साहब! यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाये तो आपको जातिवाद का सहारा लेकर खिलाड़ी सम्मानित नहीं करने पड़ेंगे। पूरा प्रदेश प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। उन्हें एक सही मौका तो दिलवाइये।

- खेल प्रतिनिधि